LOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and '(b) The charges of rampant corruption against Council for Advancement of People's Action and Rural Technology (CAPART) have not been found to have any substance.

Sectoral allocation of budget for CAPART

2097. DR. NARREDDY THULASI REDDY; Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what was the sectoral allocation of Budget for CAPART during 1990-91 and 1991-92; and

(b) what was the state-wise distribution of Budget of CAPART during the above period?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVE LOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Funds are sanc tioned by Council for Advancement of People's Action and Rural Tech-Inology \ (CAPART): under various schemes to Voluntary Organisations. Scheme-wise allocation of budget during the years 1990-91 & 1991-92 is given in the annexure

{See Appendix CLXIII, Annexure No. 39].

(b) No State-wise allocation of funds is made by the Council. Funds are sanctioned to Voluntary Organisations in different States on the basis of the Projects received A statement showing State-wise dis-tribution of sanctioned projects alongwith amount during during

is [See Appendix CLXIII, Annexure No.

40].

गांवों की दुर्दशा के लिए सरकार की जिम्मेदारी

2098. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के विशेषज्ञ दल ने गांवों की दुर्दशा के लिये सरकारी तंत्र को जिम्मेदार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विशेषज्ञ दल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) से (घ) गांव, खण्ड तथा जिला स्तर पर समन्वित विकास के लिए उपयुक्त स्व-प्रबन्ध संगठनों/निष्पादन पद्धतियों का अध्ययन और विकास करने हेतु योजना आयोग द्वारा एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह भी उल्लेख किया है कि "कानूनी जटिलताओं के अलावा सरकारी तन्त्र की बहुलता और अफसरशाही में लोगों की पहल-शक्ति को आगे नहीं आने दिया है।" कार्यदल की मुख्य सिफारिशें ये हैं :—

(1) सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना।

(2) मौजूदा नागरिक और विकास प्रशासन को एकीकृत करना।

(3) सहकारी समिति अधिनियम और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम को सरल बनाना।

(4) "ग्राम विकास संगमों" का गठन करना, जो गांव के सामूहिक सम्पत्ति संसाधनों का प्रबन्ध करने एवं सामाजिक सुधार लाने के लिए गैर-राजनैतिक संगठन होंगे और जिनके प्रति ग्राम स्तर के सभी कर्मचारी जिम्मेदार होंगे।

(5) कार्यदल ने केन्द्र में स्वयंसेवी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल संस्था के सृजन करने की सिफारिश की है।

(6) कार्यदल ने ऐसी नीति का सुझाव दिया है, जिससे विभिन्न गांवों में एक जैसे या मिलते-जुलते कार्यों में संलग्न प्रतिष्ठित तथा प्रसिद्ध संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाये, जिससे इन कार्यों के लिए आगे और संस्थाओं को प्रेरणा मिल सके। संदिग्ध संगठनों के विरुद्ध चौकसी रखने का भी इसने सुझाव दिया है।

(7) कार्यदल ने यह सुझाव दिया है कि स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रबन्ध के लिए सामुदायिक नेता तैयार करने और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने हेतु एक मुक्त नीति विकसित की जाए।

योजना आयोग ने विभागों/राज्य सरकारों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ विचार-विमर्श करने हेतु कार्रवाई शुरू की है ताकि पंचायतों सहकारी सोसायटियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से लोगों की भागीदारी को अधिक व्यापक बनाने के लिए उपयुक्त उपाय किए जा सके।

Revamping Jawahar Rozgar Yojana

2099. SHRI N. E. BALARAM: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gov ernment have decided to revamp the Jawahar Rozgar Yojana (JRY); and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRl G. VENKAT SWAMY); (a) and (b) No, Sir, Not at present. However, the Government of India has now taken up Concurrent Evaluation of Jawahar Rozgar Yojana through indepen-dejnt I. institutions [organisations ,to assess its impact in the rural areas in relation to the stated objectives of the programme. In the Concurrent evaluation, which has already been launched, the impact of the programme on the type of assets created under JRY, its usefulness to the society, in general, and to poor sections of the community, in particular and the contribution of the JRY to the welfare of the families below the poverty line are the main points for the evaluation.

'The Government will restructure the programme if the results of the Concurrent Evaluation warrant it.

Misuse of Jawahar Rozgar Yojana Fund in M.P. and U.P.

2100. SHRI SURESH PACHOURI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the reports appearing in newspapers about the misuse of funds allocated under the 'Iawaha$_r$ Rozgar Yojna' by the heads of Panchayats in various parts of the country particularly in Madhya Pradesh and Uttar Pradesh;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government have taken to prevent the misuse of funds of Jawahar Rozgatr Yojana in thel country?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) to (c) There are about 2.20 lakh Panchayats in the country. The funds are given to all the Panchayats as Jawahar Rozgar Yojana (JRY) is being implemented throughout the length and breadth of the country.

A few complaints have been received by the Government of India regarding misuse of Jawahar Rozgar Yojana funds nrovided to Gram Pradhans considering the number of Panchayats involved in implementation of the Yojana in the country, number of complaints regarding misuse of JRY funds by the Gram Pradhans are relatively very few including in the States of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. The complaints mostly relate, that the development plan